

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा

Dr. Mukesh Pancholi

(IV) कोठारी आयोग, 1964 –

सरकार ने 14 जुलाई, 1964 में डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों व प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत व नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना कार्य अक्टूबर, 1964 से शुरू किया। इसमें कुल 17 सदस्य शामिल थे।

इस आयोग ने 29 अगस्त, 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में शिक्षा के सभी परिवर्तनों और सुधारों के लिए इसका उल्लेख किया गया है।

आयोग के अनुसार शिक्षा तथा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास व प्रगति के लिए निर्णायक है। आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं -

- शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य का अनुभव व उत्पादन अनुभव आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाए।
- माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए।

- उन्नत अध्ययन केन्द्रों को अधिक सुदृढ बनाया जाए और बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी-सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल व श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए।
- शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि में शोध व इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हालांकि यह 20 वर्ष पुराना है, फिर भी अपनी खुशबू व ताजगी बनाए रखे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मुख्य रूप से इसकी सिफारिशों पर आधारित है, अतः यह शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है।

त्रिभाषी सूत्र –

वर्ष 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1968 में भारत सरकार ने 'त्रिभाषा सूत्र' की घोषणा की। 'त्रिभाषा सूत्र' में हिंदी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी व आधुनिक भारतीय भाषा (सामान्यतः दक्षिणी भाषाओं में से एक) और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी व एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की सिफारिश की गई।

नई शैक्षिक नीति, 1986 –

जनवरी सन् 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की। जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। इस समीक्षा व विश्लेषण के आधार पर शिक्षा की चुनौती – ‘A Policy Perspective’ पत्र प्रकाशित किया गया। इसी पत्र के आधार पर ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ के प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति मंडल के सामने प्रस्तुत किया गया व मई 1986 में संसद द्वारा ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ के प्रारूप को ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ 1986 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई।

इसमें यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा व्यवसाय से है, जिसके अंतर्गत जाति धर्म, लिंग व निवास के आधार पर भेद किए बिना एक निश्चित स्तर तक सभी तुलनात्मक गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 –

यह शिक्षा नीति लागू की गई, ताकि शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सकें व देश की वर्तमान व भावी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार किया जा सकें। इस नीति के अनुसार शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रसर किया गया, ताकि व शिक्षा को सार्वभौमिकरण के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

राष्ट्रीय आवश्यकताएं –

राष्ट्रीय शिक्षा का मूलाधार भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, धर्म-निरपेक्षता व लोकतंत्रात्मक समाजवाद के आदर्शों को माना गया है, इस नीति में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का प्रावधान करने का निश्चय दोहराया गया है।

राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति के लिए आवश्यक है, इस प्रयोजन से शिक्षा का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि वह –

- (i) उत्पादकता बढ़ाए, (ii) सामाजिक व राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करें (iii) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करें (iv) सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का पोषण करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की विशेषताएं –

1. राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें शैक्षिक संरचना (5) वर्षीय प्राथमिक शिक्षा (3) वर्षीय उच्च प्राथमिक (2) वर्षीय माध्यमिक (2) वर्षीय उच्चतर माध्यमिक व (3) वर्षीय प्रथम उपाधि शिक्षा से संयुक्त की गई।
2. विद्यालय स्तर की 10 वर्षीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सारे देश में समानता के आधार पर लागू किया गया व आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है, भारत के सभी भावी नागरिकों को देश के मूल्य, स्वतंत्रता, अखंडता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि जैसे मूल्यों का विकास करना है।

3. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

जीवन पर्यंत शिक्षा शैक्षिक प्रणाली का मूलभूत लक्ष्य है, प्रौढ़ों, गृहणियों, कृषकों, श्रमिकों, व्यावसायिकों को अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

भविष्य खुली व दूरस्थ शिक्षा का महत्त्व अधिक बढ़ाया जाएगा।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AITEC), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (IARC), शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् (IMC) आदि संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा, ताकि नई शिक्षा प्रणाली को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें।

5. नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने की व्यवस्था है हमारे देश में 5 वर्ग विशेष रूप से उपेक्षित है –
(i) महिलाएं, (ii) अनुसूचित जातियाँ, (iii) अनुसूचित जन-जातियां, (iv) शारीरिक विकलांग व (v) अल्पसंख्यक वर्ग।

महिला वर्ग की सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए शिक्षा को साधन बनाया जाएगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययनों को पाठ्यक्रम में प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति के लोगों को अन्य सवर्ण जाति के लोगों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएगी जिससे इस वर्ग के सभी बच्चे कम से कम 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकें।

अनुसूचित जनजाति वर्ग को शिक्षा के लिए नवीन प्राथमिक स्कूल प्राथमिकता के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में खोली जाएगी। पढ़े-लिखें आदिवासी युवाओं के प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विकलांगता वाले बालकों को आम बालकों के साथ ही पढाया जाएगा, गंभीर रूप से विकलांग के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

प्रौढ व सतत् शिक्षा के प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की कम से कम समय में पूरा करने की अनिवार्यता की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। सन् 1995 में देश में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बनाई गई 1987 की कार्य योजना में सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम शुरु किए और नवीन पहल की गई।

इसमें स्कूलों का माहौल सुधार, अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के साथ-साथ 6 से 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, जो स्कूली शिक्षा दायरे से बाहर हो गए थे। इसमें तीन प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए – Operation Black Board, शिक्षा-प्रशिक्षण क्षेत्र में सुधार व पुनर्गठन, गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम।

7. शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर व पर्यावरण का ज्ञान दिए जाने की व्यवस्था व योग शिक्षा व्यवस्था के प्रयास किए गए।

8. अध्यापकों के सेवा पूर्व व सेवारत प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंध पर विचार किया गया जिसमें विकेंद्रीकरण व स्वायत्तता की भावना का सृजन करने का प्रस्ताव किया।
10. शिक्षा नीति में राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक शिक्षा पर व्यय करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
केन्द्रीय बजट का 10% व राज्य बजट का 30% व्यय किया जाएगा।

11. शिक्षा नीति में यह भी प्रावधान किया गया कि शिक्षा नीति के आयामों, क्रियान्वयन उपलब्धियों व कमियों आदि की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष बाद की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन –

संसद ने 1986 के बजट के दौरान शिक्षा नीति, 1986 विचार-विमर्श किया व अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रारंभ में 23 कार्यदल गठित किए गए व प्रत्येक कार्यदल को शिक्षा नीति का एक विषय सौंपा गया। इन कार्यदलों को निम्न नियम सौंपे गए थे –

1. विद्यालय शिक्षा की विषय-वस्तु व प्रक्रिया
2. नागरिकों की समानता के लिए शिक्षा
3. अल्पसंख्यकों की शिक्षा

4. शिक्षा प्रणाली को लागू करना
5. विकलांगों की शिक्षा
6. अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा
7. प्रारंभिक शिक्षा (अनौपचारिक व ऑपरेशन Black Board)
8. प्रौढ़ व सतत् शिक्षा
9. शिशु देखभाल व शिक्षा
10. व्यावसायीकरण
11. माध्यमिक शिक्षा व नवोदय विद्यालय
12. उच्च शिक्षा

13. अनुसंधान व विकास
14. खुला विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा
15. तकनीकी व प्रबंध शिक्षा
16. उपाधियों को नौकरियों से पृथक् करना व जनशक्ति आयोजन
17. संचार माध्यम व शैक्षिक प्रौद्योगिकी
18. खेल, शारीरिक शिक्षा व युवा।
19. सांस्कृतिक परिपेक्ष्य तथा भाषा नीति का समन्वित
20. शिक्षक व उनका प्रशिक्षण
21. मूल्यांकन प्रणाली व परीक्षा सुधार
22. ग्रामीण संस्थाएं या विश्वविद्यालय
23. शिक्षा का प्रबंध

कार्यदलों को उनको सौंपे गए विषय के संबंध में वर्तमान स्थिति व राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशिष्ट विवरणों का उल्लेख करने का अनुरोध किया गया था, सभी कार्यदलों ने समय की कमी के बावजूद भी अपना कार्य बड़ी सावधानीपूर्वक किया व जुलाई, 1986 को रिपोर्ट पेश की। फिर इन रिपोर्टों पर मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा चर्चा की गई, चर्चाएं पूरी होने के बाद 20 जुलाई, 1986 को राज्य व संघ के शिक्षा सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया एक कार्य योजना बनाई।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में 2 अगस्त, 1986 को हुई, उसमें इस कार्ययोजना पर चर्चा की गई, विचार किया गया, उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, संसद ने पारित कर क्रियान्वयन कर दिया, इसका क्रियान्वयन 1986-87 की योजनाओं के माध्यम से हुआ।

1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के माध्यम से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना शुरू किया।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

Dr. Mukesh Pancholi

1. शैक्षिक नीति, 1986 लागू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई -

(A) इंदिरा गांधी जी

(B) राजीव गांधी जी

(C) मनमोहन सिंह जी

(D) अटल बिहारी वाजपेयी जी

Dr. Mukesh Pancholi

2. इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10 + 2 + 3 का सुझाव दिया?

(A) कोठारी आयोग

(B) शिक्षा आयोग

(C) हर्टोग समिति

(D) श्री के. एल. माली समिति

Dr. Mukesh Pancholi

3. फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है -

(A) बाँम्बे

(B) मद्रास

(C) कोलकत्ता

(D) दिल्ली

Dr. Mukesh Pancholi

4. 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना घोषित की गई -

(A) राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में

(B) शिक्षा नीति 1986 में

(C) 'प्रबुद्ध व मानवीय समाज की ओर' पत्र में

(D) इनमें से कोई नहीं

Dr. Mukesh Pancholi

5. S → राष्ट्रीय लक्ष्यों, उद्देश्यों व आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए ऐसा वातावरण / माहौल तैयार करने की आवश्यकता थी ताकि एक निश्चित स्तर तक शिक्षा के माध्यम से सभी प्रकार की गुणवत्ता प्रदान की जा सके।

R → “A Policy Perspective” पत्र प्रकाशन कर शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया, जो कि आज तक भारत की सार्वभौमिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है व लोकतंत्रात्मक समाज के आदर्शों की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से कर रहा है।

(A) S, R दोनों सही, R, S की सही व्याख्या है।

(B) S, R दोनों सही, R, S की सही व्याख्या नहीं है।

(C) S सही है, R गलत है।

(D) R सही है, S गलत है।

6. शिक्षा नीति 1986 से संबंधित गलत तथ्यों को छांटिए-

(A) इसमें 10 वर्षीय शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरे देश में समानता के आधार पर लागू किया गया।

(B) नवीन शिक्षा नीति में समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की।

(C) 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति को 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, 2 वर्षीय माध्यमिक, 2 वर्षीय उच्च माध्यमिक व 3 वर्षीय की प्रथम उपाधि से संयुक्त किया।

(D) सन् 2000 तक देश में 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का संकल्प

7. शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, किस योजना तक प्राथमिक शिक्षा 1 किमी. के दायरे में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया -

(A) सातवीं (1985 – 90)

(B) नौवीं (1997-2002)

(C) आठवीं (1992-97)

(D) दसवीं (2002-2007)

Dr. Mukesh Pancholi

8. कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया व कब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की?

(A) 1964 July, Oct. 1964

(B) July 1964, Aug. 1966

(C) Aug. 1964, Oct. 1966

(D) Oct. 1964, Aug. 1966

Dr. Mukesh Pancholi

9. कोठारी आयोग संबंधित है?

- (A) राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा, सिद्धांत व नीतियों की रूपरेखा से
- (B) ग्रामीण शिक्षा में सुधार से
- (C) तकनीकी व उच्च शिक्षा में संभावनाओं का पता लगाने व सुझाव से संबंधित
- (D) उपरोक्त सभी

Dr. Mukesh Pancholi

10. कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए -

- (A) भावात्मक
- (B) औपचारिक
- (C) सामान्य
- (D) व्यावसायिक

Dr. Mukesh Pancholi

11. कार्यानुभव, उत्पादन अनुभव को शिक्षा से जोड़ने का विचार किसने दिया?

(A) राधाकृष्णन आयोग

(B) कोठारी आयोग

(C) संपूर्णानंद आयोग

(D) जाकिर हुसैन समिति

Dr. Mukesh Pancholi

12. त्रिभाषा सूत्र की घोषणा कब की गई -

(A) 1968

(B) 1966

(C) 1986

(D) 1964

Dr. Mukesh Pancholi

13. कथन → प्रौढ़, महिला, श्रमिक, गृहिणियों आदि को अपनी क्षमतानुसार व सुविधानुसार शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सके।
कारण → शिक्षा नीति 1986 में सार्वभौमिक शिक्षा के साथ-साथ जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली को भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है?

- (A) कथन व कारण दोनों एक-दूसरे से संबंधित है, स्पष्ट व्याख्या नहीं करते।
- (B) कथन व कारण दोनों सही है व एक-दूसरे की स्पष्ट व्याख्या करते हैं।
- (C) कथन सही है, परन्तु कारण गलत है।
- (D) कारण सही है, परन्तु कथन सही नहीं है।

14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए-

- I. शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक करने का प्रस्ताव स्वीकार।
- II. केन्द्रीय बजट का 10% व राज्य बजट का 30% व्यय किया जाएगा शिक्षा पर।
- III. शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, में आर ही बाधाओं की समीक्षा हर 3 वर्ष बाद की जाएगी।

- (A) I, II, III
- (B) II, III
- (C) I, II
- (D) I, III

15. शिक्षा नीति 1986 में तीन प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए, उनमें शामिल नहीं है -

(A) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

(B) शिक्षा-प्रशिक्षण क्षेत्र में सुधार

(C) गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम

(D) विवेकानंद मॉडल स्कूलों की स्थापना

Dr. Mukesh Paricholi